EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

## Monday, 22 July , 2024

## Edition: International Table of Contents


| | |
|---|---|
| **Page 04**<br>**Syllabus : : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था** | भारत के परिधान निर्यात की समस्याएँ स्वयं ही रिपोर्ट द्वारा उत्पन्न की गई हैं |
| **Page 07**<br>**Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी** | डायसन क्षेत्र ऊर्जा भक्षक है |
| **Page 07**<br>**Syllabus : GS 1 : भूगोल** | भारत से परे डेटा अंतराल मानसून पूर्वानुमानों को रोक रहा है |
| **Page 09**<br>**Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध** | क्वाड और ब्रिक्स दोनों का महत्व |
| **समाचार में महत्वपूर्ण दिन** | राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 2024 |
| **Page 08 : संपादकीय विश्लेषण:**<br>**Syllabus : GS: 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था - विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।** | बेरोज़गारी का मुकाबला करने के लिए महिला रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करें |
| **मैपिंग** | विषय:<br>भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ |

## Page 04 : GS 3 : Indian Economy – Effects of liberalisation on the economy

भारत का परिधान निर्यात, जिसका मूल्य 2023-24 में 14.5 बिलियन डॉलर है, उच्च आयात शुल्क, जटिल प्रक्रियाओं और पुराने नियमों के कारण बाधित है।

- वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी भारत से आगे निकल गए हैं, बढ़ते आयात और घरेलू आपूर्ति के मुद्दों ने समस्या को और बढ़ा दिया है। वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना भी निवेश आकर्षित करने में विफल रही है।

# India's garment export woes self-inflicted: report

At $14.5 billion, exports from the job-intensive sector were lower in 2023-24 than a decade earlier, owing to barriers on raw material imports and difficult customs, trade procedures, says think tank

**Vikas Dhoot**
NEW DELHI

Exports from India's labour-intensive garment sector, which have been losing ground to rivals such as Vietnam and Bangladesh and were lower than the 2013-14 levels last year, have been dented more by the country's high duties and barriers on raw material imports along with difficult customs and trade procedures, rather than other nations' competitive strengths, a research report has flagged.

India's garment exports in 2023-24 stood at $14.5 billion, compared with $15 billion in 2013-14. Between 2013 and 2023, garment exports from Vietnam have grown nearly 82% to hit $33.4 billion while that of Bangladesh has grown nearly 70% to hit $43.8 billion. China exported about $114 billion of garments in the same year, nearly a quarter lower than a decade earlier.

A production-linked incentive (PLI) scheme for textiles launched by the Centre in 2021 has failed to gain traction with investors and needs significant modifications to be effective, the think tank, Global Trade Research Initiative (GTRI), has noted in a report titled "How Complex Procedures, Import Restrictions and Domestic Interests Hinder India's Garments Exports".

The report pointed out that recent quality control orders have complicated the process of bringing in essential raw materials. AFP

The report has also raised concerns about a steady rise in India's garments and textiles imports in recent years, which had grown to almost $9.2 billion in the calendar year 2023. It warned that this tally could rise faster if the export slide is not arrested, especially with firms like Reliance Retail expected to kick off sales of Chinese brands such as Shein in the country.

"Complex procedures, import restrictions and domestic vested interests are holding up Indian garment export growth. At the root of the exporters' problem is difficulty in obtaining quality raw fabric particularly synthetic fabric," the report said, adding that Bangladesh and Vietnam do not suffer from these complexities, while Indian firms have to "waste time and money" on them.

The report, based on interactions with small, medium-sized, and large garment exporters, pointed out that recent quality control orders, or QCOs, issued for fabric imports have complicated the process of bringing in essential raw material. This is pushing up costs for exporters who have to rely on pricier options from domestic firms who dominate the market for raw materials like polyester staple fibre and viscose staple fibre.

"This scenario forces exporters to use expensive domestic supplies, making Indian garments overpriced," it explained.

Moreover, the procedures laid down by the Directorate General of Foreign Trade and Customs are archaic, requiring exporters to meticulously account for every square centimetre of imported fabric, buttons, and zippers, ensuring these are used in the production process and reflected in export product description, the report said, mooting a comprehensive overhaul to change the *status quo*.

**मौजूदा निर्यात प्रदर्शन:**

- 2023-24 में भारत का परिधान निर्यात कुल 14.5 बिलियन डॉलर रहा, जो 2013-14 में 15 बिलियन डॉलर से कम है।
- इसी अवधि में वियतनाम का परिधान निर्यात लगभग 82% बढ़कर 33.4 बिलियन डॉलर हो गया, और बांग्लादेश का निर्यात लगभग 70% बढ़कर 43.8 बिलियन डॉलर हो गया।
- चीन का परिधान निर्यात लगभग 114 बिलियन डॉलर रहा, जो एक दशक पहले की तुलना में लगभग 25% कम है।

**उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से जुड़ी समस्याएँ:**

- 2021 में शुरू की गई वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना ने निवेशकों की खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
- वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआई) के अनुसार, इस क्षेत्र को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए योजना में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है।

**बढ़ते आयात और घरेलू चिंताएँ:**

- भारत का परिधान और वस्त्रों का आयात 2023 में लगभग 9.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
- यदि निर्यात में गिरावट जारी रहती है, खासकर भारत में शीन जैसे चीनी ब्रांडों के आने से, तो यह आँकड़ा और बढ़ सकता है।

**जटिल प्रक्रियाएँ और आयात प्रतिबंध:**

- भारतीय परिधान निर्यातकों को जटिल आयात प्रक्रियाओं और प्रतिबंधों के कारण गुणवत्तापूर्ण सिंथेटिक कपड़े प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- बांग्लादेश और वियतनाम के निर्यातकों को ऐसी जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रक्रियाएँ अधिक कुशल और कम खर्चीली हो जाती हैं।

**गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) और उच्च लागत:**

- हाल ही में QCO ने आवश्यक कच्चे माल के आयात को जटिल बना दिया है, जिससे निर्यातकों की लागत बढ़ गई है।
- भारतीय निर्यातकों को पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर और विस्कोस स्टेपल फाइबर जैसे कच्चे माल के लिए अधिक महंगे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे भारतीय परिधानों की कीमत कम प्रतिस्पर्धी हो जाती है।

**पुरानी प्रक्रियाएँ और प्रशासनिक बोझ:**

- विदेश व्यापार और सीमा शुल्क महानिदेशालय पुरानी प्रक्रियाओं को लागू करता है, जिसके तहत आयातित सामग्रियों के प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर के लिए विस्तृत लेखा-जोखा रखना आवश्यक है।
- ये प्रक्रियाएँ निर्यातकों पर महत्वपूर्ण प्रशासनिक बोझ डालती हैं, जिससे अकुशलता और अतिरिक्त लागतें बढ़ती हैं।

**सुधार के लिए सिफारिशें:**

- रिपोर्ट मौजूदा प्रक्रियाओं और नीतियों में व्यापक बदलाव का सुझाव देती है।
- आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और नियामक प्रथाओं को अद्यतन करने से लागत कम करने और निर्यात दक्षता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

- वैश्विक बाजार में भारतीय परिधानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इन प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

## Mains Practice Question

**प्रश्न: भारत के परिधान निर्यात क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुधार सुझाएँ। आयात शुल्क, प्रक्रियागत जटिलताओं और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित किया है?**

## Page 07 : GS 3 : Science & Technology

डायसन स्फीयर फ्रीमैन डायसन द्वारा प्रस्तावित एक सैद्धांतिक संरचना है, जिसका उद्देश्य उन्नत सभ्यताओं के लिए किसी तारे की ऊर्जा को एकत्रित करना है।

- इसमें किसी तारे के चारों ओर सौर पैनलों का एक खोल या झुंड होता है, और इसकी उपस्थिति का पता अत्यधिक अवरक्त विकिरण द्वारा लगाया जा सकता है। हाल ही में की गई खोजों में कई तारों से अस्पष्टीकृत अवरक्त उत्सर्जन पाया गया है।

**WHAT IS IT?**

# Dyson sphere: an energy devourer

**Arkatapa Basu**

Imagine you are an astronomer looking deep into space in search of extraterrestrial life. You spot a star that is emitting infrared radiation in anomalous fashion. You zoom in and see a swarm of solar panels covering the star like a shell, quietly collecting an enormous amount of solar energy from the star. Et voila: you have found a Dyson sphere.

The Dyson sphere is named after theoretical physicist Freeman Dyson (1923-2020), who hypothesised its existence. He said that technologically advanced civilisations will have such a tremendous demand for energy that they will have to harness the entire radiative power of a star, using solar energy collectors arranged in a sphere around the orb.

Dyson also figured that these spheres would emit excess heat from the star as infrared radiation, which he said astronomers could look for as an indirect sign of intelligent life — especially life capable of building such megastructures.

Of course, not all unusual infrared radiation emissions are indicative of Dyson spheres. In May this year, scientists set out to look specifically for the signature of

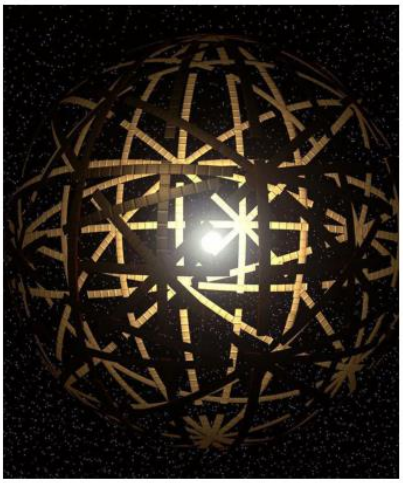

Freeman Dyson said that technologically advanced civilisations will harness the entire radiative power of a star.

Dyson spheres. They scanned 5 million stars within 1,000 light years of the earth. After analysing this data, they found seven stars whose infrared radiation they could not explain. There is no conclusive evidence still, but might one of these seven stars have a Dyson sphere surrounding it?

**For feedback and suggestions** for 'Science', please write to **science@thehindu.co.in** with the subject 'Daily page'

**डायसन स्फीयर क्या है:**

- डायसन स्फीयर भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन द्वारा प्रस्तावित एक सैद्धांतिक मेगास्ट्रक्चर है।
- इसका उद्देश्य किसी तारे के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन को कैप्चर करना और उसका उपयोग करना है, ताकि अत्यधिक उन्नत सभ्यता की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।
- इस अवधारणा में तारे के चारों ओर सौर पैनलों या ऊर्जा संग्राहकों का एक खोल या झुंड बनाना शामिल है।
- एकत्रित सौर ऊर्जा को सभ्यता के लिए उपयोगी शक्ति में परिवर्तित किया जाएगा।
- डायसन स्फीयर से इंफ्रारेड विकिरण के रूप में अतिरिक्त गर्मी निकलने की उम्मीद है, जिसे खगोलविद पहचान सकते हैं।
- इस विचार से पता चलता है कि अगर हम असामान्य इंफ्रारेड हस्ताक्षरों का पता लगाते हैं, तो यह ऐसी संरचना की उपस्थिति और विस्तार से, बुद्धिमान जीवन का संकेत दे सकता है।
- 1,000 प्रकाश वर्ष के भीतर सितारों की हाल की खोजों ने अस्पष्टीकृत इंफ्रारेड उत्सर्जन वाले सात सितारों की पहचान की है, जो संभावित रूप से डायसन स्फीयर की ओर इशारा करते हैं, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है।

**फ्रीमैन डायसन (1923-2020) कौन थे?**

- डायसन एक प्रसिद्ध ब्रिटिश-अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सॉलिड-स्टेट फिजिक्स और खगोल विज्ञान में अपने काम के लिए जाने जाते थे।
- 15 दिसंबर, 1923 को इंग्लैंड में जन्मे, उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें डायसन स्फीयर अवधारणा भी शामिल है - एक काल्पनिक संरचना जो किसी तारे को घेरकर उसके ऊर्जा उत्पादन को पकड़ सकती है। व
- ह एक प्रमुख भविष्यवादी और लेखक भी थे, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा, अलौकिक जीवन और मानवता के भविष्य पर विचारों की खोज की।
- डायसन ने अपने करियर का अधिकांश समय प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में बिताया और विज्ञान के प्रति अपने अंतःविषय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे।

## UPSC Prelims PYQ : 2015

**प्रश्न: 'गोल्डीलॉक्स ज़ोन' शब्द अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है**

(a) पृथ्वी की सतह के ऊपर रहने योग्य क्षेत्र की सीमाएँ
(b) बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के अंदर के क्षेत्र
(c) बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज
(d) कीमती धातुओं वाले उल्कापिंडों की खोज

**उत्तर: c)**

2024 के मानसून ने अनियमित वर्षा वितरण के साथ अप्रत्याशित पैटर्न दिखाए हैं। जबकि पूर्वानुमान प्रत्याशित ला नीना स्थितियों पर आधारित थे, वास्तविक वर्षा अनियमित रही है।

- कृषि और जल प्रबंधन के लिए सटीक स्थानीय पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। बेहतर पूर्वानुमानों के लिए उपमहाद्वीप में मौसम की निगरानी का विस्तार और डेटा संग्रह में सुधार की सिफारिश की जाती है।

# Data gaps beyond India are holding monsoon forecasts back

The convenience of using the 'all-India monsoon rainfall' index for seasonal outlooks is undermined by the uncertainty India's farmers face at local levels. Our forecasts of rain weeks ahead of a date are getting better but they also increase the demand for even more accurate hyperlocal forecasts

Raghu Murtugudde

We are now in the middle of the monsoon of 2024. The season began on May 30 as expected, but its evolution thus far has sprung some surprises. The rainfall distribution looks as patchy as ever, though with some unexpected patterns. The seasonal outlook provided by the India Meteorological Department (IMD) predicted normal to above-normal rainfall based on the expectation that a La Niña is likely. La Niña, however, appears to be playing truant.

After onset, the northward movement of the monsoon trough seemed to be quite rapid. But then the trough stalled and produced a fairly dry June over large swathes of the country. The entire Western Ghats received below-normal rainfall into July. An unusual pattern of excess rain stretching from south to north persists to this day, with dry patches over large parts of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and Odisha, as well as north-western India into Jammu and Kashmir.

## A useful index with disclaimers

I have used this analogy before, and it still works well. As the sun crosses into the northern hemisphere and starts warming the Indian subcontinent like a popcorn kettle, monsoon systems pop like kernels of corn in the kettle. The temperature inside the kettle will be essentially uniform, but kernels will still pop randomly, here and there.

These kernels are like the rainfall: its patchy pattern is visible in day-to-day data as well as data averaged over the whole season and even over a whole decade.

However, the convenience of using the 'all-India monsoon rainfall' index for seasonal outlooks – as the IMD does – is undermined by the uncertainty India's farmers face at the local level. Our forecasts of rain days or weeks ahead of a given date are getting better, but they concomitantly increase the demand for, and value of, even more accurate and hyperlocal forecasts.

This demand is not only from farmers but also from water managers and energy companies, among others. We need a broader perspective of the monsoon circulation to help understand where the limitations exist and how they can be resolved.

## The circulation beyond India

People know the summer monsoon as the "southwest monsoon" because the winds sweep in from the southwest over the Arabian Sea into mainland India, across the Western Ghats. The western edge of the winds grazes the African highlands, and some experts have often argued that they are critical for steering the south westerly winds. The active Bay of Bengal, which is full of convective events, can be expected to 'pull' the winds towards India as well.Convection in the atmosphere refers to rain events that release condensation heat.

The heating over West Asia and even the dust from the deserts there contribute to the monsoon circulation, and its variability, as well as the changes it is experiencing due to global warming. Pakistan is very much a part of the monsoon circulation and it experiences high rainfall variability. This is because the edges of the monsoon circulation tend to be highly variable.

The land encompassed by the Himalayan foothills, and thus Nepal and Bhutan, as well as the eastern edge of the Bay of Bengal (including Myanmar), is also involved in regulating the monsoon and the transfer of its heat to the Indian subcontinent. Bangladesh is, of course, ensconced between Northeast India and mainland India. We don't pay attention to the role of heating over Bangladesh or the ocean-land-atmosphere dynamics that create the beautiful monsoon and its heartbreaking vagaries every year.

The heating centres over the subcontinent are very strong, and they maintain a sustained demand for moisture to sustain the convection centres. Indeed, the circulation that sweeps the oceans and the subcontinent cannot be represented accurately in rainfall models unless we capture all the heating centres from Pakistan and West Asia in the west to Myanmar in the east, and the Indian Ocean from about 10 degrees south to its northern edge against the subcontinent.

People know the summer monsoon as the 'southwest monsoon' because the winds sweep in from the southwest over the Arabian Sea into mainland India, across the Western Ghats. PTI

> After onset, the northward movement of the monsoon trough seemed to be quite rapid. But then the trough stalled and produced a fairly dry June over large swaths of the country. The entire Western Ghats received below-normal rainfall into July

## Detail gaps beyond India's borders

As hard as the IMD and its labs are working to improve their monsoon forecasting abilities at all timescales, their efforts are also undermined by a lack of rainfall and other weather data over parts of the subcontinent beyond India. Satellites can help to some extent, but the amount of data available in near real-time to initiate forecasts is often quite inadequate.

These rainfall models are global for most subcontinent-scale forecasts, even though the IMD also develops regional model forecasts at the level of cities, and at the national scale. The global models ingest data about the oceans and the planetary atmosphere to initiate forecasts, and the volume of data can appear to be large and adequate – but this is often not the case.

## Monitoring the whole subcontinent

India has been fortunate enough to have a rainfall monitoring network since the 19th century, and the advantages are now bearing fruit with investments in forecasting infrastructure. At this point, we need a few important steps to reach the next level in forecast accuracy. This is also essential to sustain continuous economic growth for India, especially in terms of food, water, and energy security.

In fact, even our national security depends heavily on weather and climate forecasts – for India as well as for the country's more climate-vulnerable neighbours. Debilitating natural disasters can quickly turn into national security concerns, especially with some neighbours having to seek aid from non-allies.

India does share its forecasts with some countries, but it may benefit more by extending this strategy to also establish a broad network to monitor weather and climate across the subcontinent. Improved forecasts for the subcontinent will make everybody safer and less vulnerable. This can only mean better opportunities for safety for all, including food, water, and energy, as well as better health.

*(Raghu Murtugudde is a professor, IIT Bombay, and Emeritus Professor, University of Maryland.)*

### THE GIST

The demand for accurate forecasts is not only from farmers but also water managers and energy companies. We need a broader perspective of the monsoon circulation to help understand where the limitations exist

The heating centres over the subcontinent maintain a demand for moisture. Circulation from the oceans and subcontinent can't be represented accurately unless we capture data from Pakistan, West Asia, Myanmar, and the Indian Ocean

India has had rainfall monitoring since the 19th century. Now we need to take a few important steps to reach the next level in forecast accuracy. This is essential to sustain economic growth

**मानसून का विकास:**

- 2024 का मानसून सीजन 30 मई को उम्मीद के मुताबिक शुरू हुआ, लेकिन इसने अप्रत्याशित पैटर्न दिखाए हैं।
- वर्षा वितरण अत्यधिक अनियमित रहा है, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई है और अन्य क्षेत्रों में काफी सूखा रहा है।
- मानसून की गर्त के तेजी से उत्तर की ओर बढ़ने के बाद, यह रुक गया, जिससे कई क्षेत्रों में जून में सूखा रहा। पश्चिमी घाट में सामान्य से कम वर्षा हुई है।

**क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न:**

- दक्षिण से उत्तर की ओर अत्यधिक वर्षा का एक असामान्य पैटर्न देखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे क्षेत्रों में सूखे पैच का अनुभव हुआ है।
- यह अनियमित वितरण ला नीना स्थितियों पर आधारित पूर्वानुमानों के विपरीत है, जो असंगत प्रतीत होते हैं।

**पूर्वानुमान लगाने की चुनौतियाँ:**

- मानसून प्रणाली के केतली में दानों की तरह फूटने की उपमा वर्षा की अंतर्निहित अनियमितता को दर्शाती है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा उपयोग किया जाने वाला 'अखिल भारतीय मानसून वर्षा' सूचकांक सामान्य दृष्टिकोण के लिए उपयोगी है, लेकिन स्थानीय विविधताओं को ध्यान में नहीं रखता है।
- वर्षा की जटिल और अनियमित प्रकृति के कारण किसानों, जल प्रबंधकों और ऊर्जा कंपनियों द्वारा सटीक, अति स्थानीय पूर्वानुमानों की मांग बढ़ रही है।

**वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव:**

- दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर की हवाओं, बंगाल की खाड़ी की संवहनीय घटनाओं और पश्चिम एशिया और रेगिस्तानों से होने वाली गर्मी सहित विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है।
- मानसून परिसंचरण में परिवर्तनशीलता हिमालय की तलहटी, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश में गर्मी से भी प्रभावित होती है।
- मानसून की जटिलता के कारण सटीक पूर्वानुमान के लिए इन व्यापक प्रभावों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

**डेटा और पूर्वानुमान सीमाएँ:**

- पूर्वानुमान में सुधार के लिए IMD के प्रयासों के बावजूद, उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों से वास्तविक समय की वर्षा के डेटा और मौसम संबंधी टिप्पणियों की कमी सटीकता में बाधा डालती है।
- पूर्वानुमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले वैश्विक मॉडल में अक्सर सटीक भविष्यवाणियों के लिए पर्याप्त डेटा की कमी होती है, खासकर स्थानीय पैमानों के लिए।

**निगरानी और सहयोग की आवश्यकताएँ:**

- भारत में वर्षा निगरानी नेटवर्क ऐतिहासिक रूप से मौजूद है, लेकिन बेहतर सटीकता के लिए पूर्वानुमान बुनियादी ढांचे में और निवेश की आवश्यकता है।
- आर्थिक विकास, खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है।
- पूरे उपमहाद्वीप में मौसम और जलवायु निगरानी नेटवर्क का विस्तार करने से सुरक्षा बढ़ सकती है और भेद्यता कम हो सकती है, जिससे क्षेत्र के सभी देशों को लाभ होगा।

**रणनीतिक सिफारिशें:**

- पूरे उपमहाद्वीप में मौसम और जलवायु निगरानी के लिए एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करें।
- स्थानीय और क्षेत्रीय पूर्वानुमान सटीकता को बढ़ाने के लिए डेटा संग्रह और पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार करें।
- पूर्वानुमान साझा करने और समग्र क्षेत्रीय सुरक्षा और लचीलापन में सुधार करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ अधिक व्यापक रूप से सहयोग करें।

## UPSC Mains PYQ : 2017

**प्रश्न:** मानसूनी जलवायु को कौन सी विशेषताएं सौंपी जा सकती हैं जो मानसून एशिया में रहने वाली हमारी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी को भोजन उपलब्ध कराने में सफल होती है?

## Page : 09 : GS 2: International Relations

भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और उभरते बहुपक्षीय ढाँचों द्वारा चिह्नित वैश्विक गतिशीलता में बदलाव के बीच क्वाड और ब्रिक्स में भारत के रणनीतिक गठबंधन ने प्रमुखता हासिल की है।

- ये जुड़ाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के बीच अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाता है, सुरक्षा अनिवार्यताओं को बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ संतुलित करता है।

# The importance of both Quad and BRICS

**T.S. Tirumurti**

Foreign Service Officer who was India's Permanent Representative to the UN, New York, and India's Sherpa for BRICS

The Quad Foreign Ministers' meeting in Japan end-July, after a long gap of 10 months, comes at a time when the United Nations Security Council (UNSC) is paralysed and its reform nowhere in sight, international law is violated with impunity both in the Ukraine war and in the assault on Gaza by Israel, an axis of Russia, China, North Korea, and Iran is gaining traction, and Chinese influence is growing not just in the Indo-Pacific, but elsewhere too.

The U.S. has, in turn, realised that it needs not just allies, but also credible partners in its security architecture, including in the Indo-Pacific, and reached "across the aisle" to "non-ally" countries like India to partner with them in smaller pluri-lateral groupings and joint security initiatives. Further, ASEAN countries are getting increasingly vulnerable, with South China Sea remaining a flashpoint.

While India is a member of many pluri-lateral groups on both sides of the geo-strategic "divide", its engagement in Quad and with BRICS present the country with interesting, and sometimes contrasting, dilemmas.

India has enthusiastically embraced Quad and its strategic objectives. U.S. President Joe Biden's belief in the Quad has given it the necessary fillip at the highest level since 2021. The fact that India, during its presidency of the UNSC in August 2021, held a high-level virtual event on 'Enhancing Maritime Security', presided over by Prime Minister Narendra Modi and attended by Russian President Vladimir Putin, among others, indicates the importance India attaches to strengthening maritime security in the Indo-Pacific and beyond.

**India's role in the Quad**

While Quad has always had a geopolitical security objective vis-à-vis China, India's vision goes beyond this narrow thrust to a much broader redrawing of the security and techno-economic architecture of the Indo-Pacific region. With Quad now working on reorientation of global supply chains of critical technologies and on a range of areas of direct strategic relevance to the region, including digital, telecom, health, power, and semi-conductors, it has underlined that development too has a security perspective which cannot be ignored. India, in its turn, has benefited through enhanced bilateral relations with Quad partners, especially the U.S.

On the other hand, the formation of AUKUS with the U.S., Australia, and the U.K., with a view to enhance their military capabilities, especially Australia's with nuclear submarines, has put securitisation of the Indo-Pacific region and deterrence of China at the centre. The Ukraine war and enhanced focus on NATO has made the West look at Asia too through a military lens. AUKUS may well suit India's geo-strategic interests, but India's reluctance to go the whole nine yards in embracing a purely security vision for Quad is seen as a dampener, in spite of the Indian External Affairs Minister clarifying that Quad is not an Asian NATO and India is not a treaty ally unlike the other three. In fact, I used to tell my Quad colleagues in the UN that the only value-add we have in Quad is India. Instead of factoring in India's viewpoint, if they merely want to convert India to their cause, then they are wasting the opportunity to become inclusive and enhance their overall impact in the region, which includes developing countries with differing compulsions, not all of which are military-centric.

India's independent policy of close relations with Russia and calling for a diplomatic solution to the Ukraine war, both of which are frowned upon by the West, do not distract India from strengthening the Quad. Some Quad members and European countries are themselves enhancing their bilateral engagement with China, underlining their differing bilateral and regional compulsions.

Against the backdrop of India's enthusiastic engagement with Quad, its engagement with BRICS presents a different conundrum. India was an enthusiastic founder of BRICS. In fact, at the 10th annual summit of the BRICS in 2018 in Johannesburg, South Africa, it was Mr. Modi who reminded the leaders that BRICS was founded to reform the multilateral system and proposed for the first time his vision of "reformed multilateralism." However, India's participation in BRICS has fluctuated from enthusiastic to lukewarm. While BRICS' initiatives such as New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement have been pioneering, the attempt by China to use BRICS to grandstand and push its world view on the Global South and now, to push back the West has made India wary of giving BRICS a higher profile.

**The potential of BRICS**

India had, consequently, been reluctant to expand BRICS. In fact, in 2018, Mr. Putin too underlined his reluctance to expand BRICS by quoting former South African President Nelson Mandela: "After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb." But after Quad and the situation in Ukraine, Russia too realised the potential of BRICS, which includes pushing back the West, and lined up behind China. The change of guard in Brazil leaves India as the lone member to push back China. A reluctant India decided to accept BRICS's expansion than oppose it and now many more countries are reportedly waiting to join. Even if India has the best of bilateral relations with all the new members, we need to make sure it all adds up to support for India inside BRICS. For this, India cannot afford to be ambivalent about BRICS any more. To counter moves to take BRICS in a direction India does not like, we need to be more engaged, not less. With India being the only country common to both Quad and BRICS, the country cannot afford to downplay one for the other.

With India being the only country common to both Quad and BRICS and a founding member of both, it cannot afford to downplay one for the other

## क्वाड क्या है?

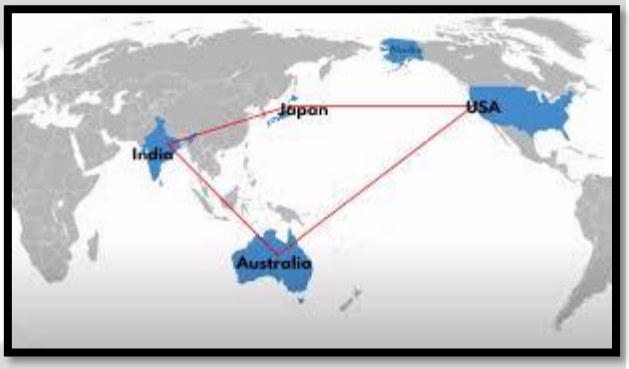


- यह चार लोकतंत्रों का समूह है - भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान।
- चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते एक समान आधार पाते हैं और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं।
- इसका उद्देश्य एक "स्वतंत्र, खुला और समृद्ध" हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है।
- क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया के चीन के दबाव के कारण इससे बाहर निकलने के कारण यह विचार आगे नहीं बढ़ सका।
- अंततः 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथ आए और इस "चतुर्भुज" गठबंधन का गठन किया।

## क्वाड में भारत की भूमिका:

- सामरिक भागीदारी: क्वाड में भारत की भागीदारी अन्य सदस्य देशों के साथ अपनी सामरिक भागीदारी को बढ़ाती है, जिससे समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सहयोगात्मक प्रयास संभव होते हैं।
- इंडो-इन-पैसिफिक नीति का निर्माण: क्वाड का एक प्राथमिक उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों को कम करना है।
- भारत क्षेत्रीय सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका निभाने की स्थिति में है।
- आर्थिक सहयोग: क्वाड राष्ट्र आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें 'मलक्का जलडमरूमध्य' में बुनियादी ढाँचा विकास और इंडो-पैसिफिक देशों के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्प शामिल हैं।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत: भारत ने मानवीय प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसका उदाहरण उसका ऑपरेशन संजीवनी है, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान कई इंडो-पैसिफिक देशों को चिकित्सा सहायता प्रदान की।

## ब्रिक्स क्या है?

### के बारे में:

- ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त नाम है।
- ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने 2023 में की थी, और रूस अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

**ब्रिक्स का गठन:**

- समूह का गठन पहली बार अनौपचारिक रूप से 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जी8 (अब जी7) आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) के नेताओं की बैठक के दौरान किया गया था, जिसे बाद में 2006 में न्यूयॉर्क में पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था।
- 2009 में, उद्घाटन ब्रिक शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। अगले वर्ष (2010) दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और ब्रिक्स नामक समूह का गठन हुआ।

**ब्रिक्स पर सकारात्मक पहलू**

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना: ब्रिक्स शीत युद्ध के बाद के युग में एक महत्वपूर्ण गैर-पश्चिमी वैश्विक पहल का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों से प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ ला सकता है।
- वैश्विक शासन में आवाज़ों को बढ़ाना: ब्रिक्स की आबादी दुनिया की लगभग 40% है, इसलिए ब्रिक्स देश वैश्विक शासन में अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं और इस समूह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अपने विकल्पों का विस्तार कर सकते हैं।
- आर्थिक लचीलापन बढ़ाना: चल रही COVID-19 महामारी के बावजूद, ब्रिक्स अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक लचीलापन बढ़ाने में एक अधिक प्रभावी और कुशल संस्था के रूप में उभरा है।
- वैकल्पिक वित्तीय तंत्रों की खोज: ब्रिक्स ने वैकल्पिक वित्तीय तंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA)।
- G20 में ब्रिक्स समूह की भूमिका: ब्रिक्स समूह ने लगातार G20 एजेंडे में विकास के मुद्दों को शामिल करने पर जोर दिया है। उनका तर्क है कि जी-20 को विकासशील देशों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए, खास तौर पर बुनियादी ढांचे में निवेश और सामाजिक क्षेत्र के समर्थन के मामले में।
- सतत विकास को बढ़ावा देना: ब्रिक्स देशों ने हरित और सतत विकास के लिए जिम्मेदार वित्तपोषण के महत्व पर जोर दिया है।
- एनडीबी जैसी पहल टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो एसडीजी लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में मदद करेगी।

## UPSC Prelims PYQ : 2014

**प्रश्न: ब्रिक्स के नाम से जाने जाने वाले देशों के समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था।

2. दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर: (b)**

## UPSC Mains PYQ : 2020

**प्रश्न: चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) वर्तमान समय में एक सैन्य गठबंधन से एक व्यापार ब्लॉक में परिवर्तित हो रहा है, चर्चा करें।**

# Important Day In News : National Flag Day, 2024

## 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।

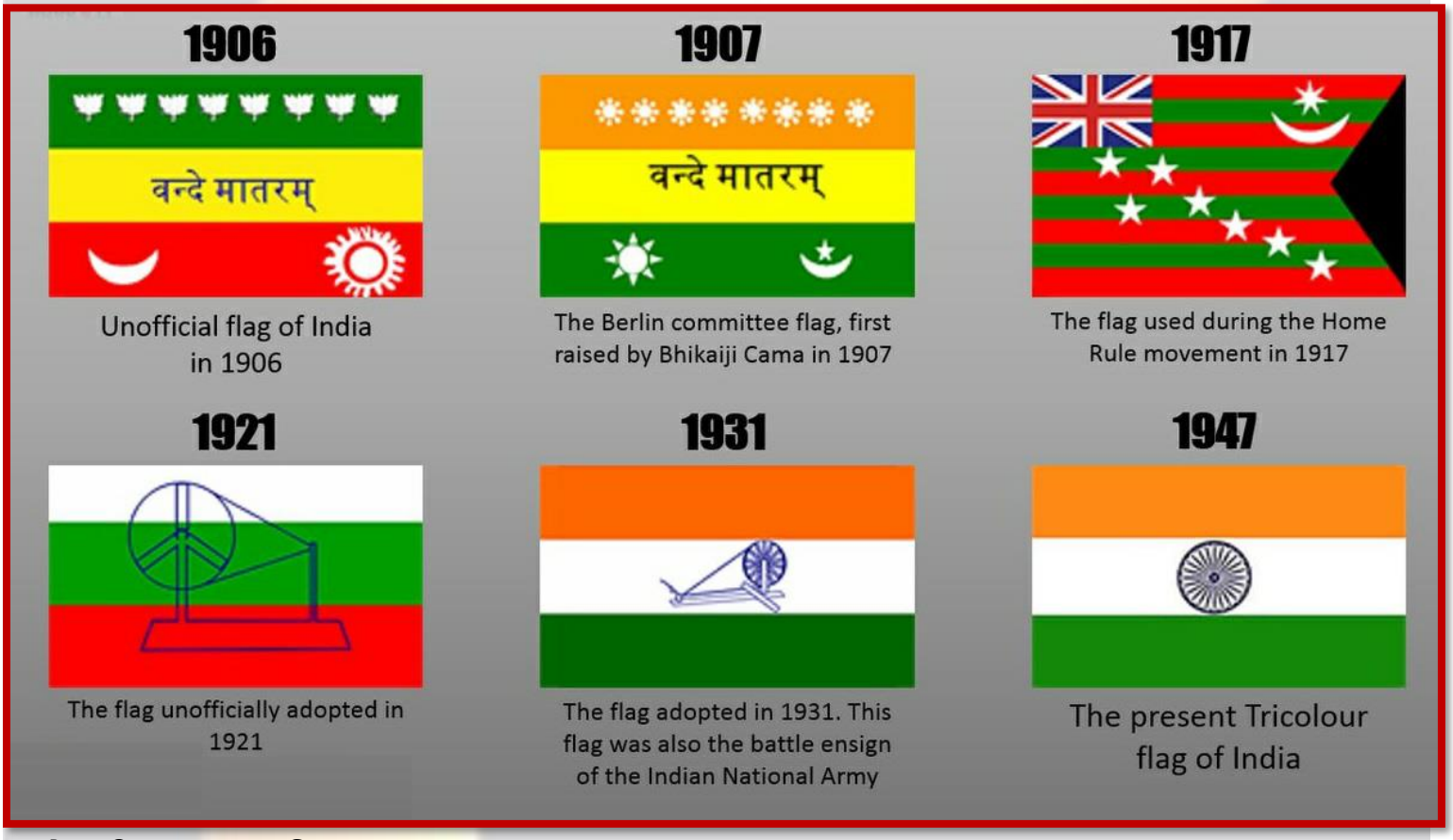


### हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास

- कोलकाता में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन (1906):
- भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त, 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर (ग्रीन पार्क) में फहराया गया था।
- ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिसके बीच में "वंदे मातरम" लिखा हुआ था।
- प्रतीकात्मकता: लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र के प्रतीक शामिल थे, जबकि हरी पट्टी में आठ आधे खुले कमल थे।
- ऐसा माना जाता है कि इस ध्वज को स्वतंत्रता कार्यकर्ता सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने डिज़ाइन किया था।

### जर्मनी में भारतीय ध्वज:

- 1907 में, मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया।
- इस घटना ने पहली बार किसी विदेशी देश में भारतीय ध्वज फहराया।

**होम रूल आंदोलन ध्वज:**

- डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में होम रूल आंदोलन के हिस्से के रूप में एक नया ध्वज पेश किया।
- ध्वज में लाल और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थीं, जिसमें सप्तऋषि के आकार में सात तारे थे।
- इसमें एक शीर्ष कोने में एक सफेद अर्धचंद्र और तारा था, और दूसरे में यूनियन जैक था।

**पिंगली वेंकैया द्वारा संस्करण:**

- भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को आधुनिक भारतीय तिरंगे के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है।
- वेंकैया की पहली मुलाकात महात्मा गांधी से दूसरे एंग्लो-बोअर युद्ध (1899-1902) के दौरान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी।
- उन्होंने व्यापक शोध किया और 1916 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें भारतीय ध्वज के लिए संभावित डिजाइन शामिल थे।
- 1921 में बेजवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में, वेंकैया ने गांधी को एक बुनियादी ध्वज डिजाइन का प्रस्ताव दिया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल और हरे रंग की दो पट्टियाँ थीं।

**राष्ट्रीय ध्वज पर जवाहरलाल नेहरू का संकल्प**

- भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प पेश किया:
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया (केसरी), सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा।
- सफेद पट्टी के मध्य में एक गहरे नीले रंग का चक्र होगा जो चरखे का प्रतिनिधित्व करेगा।
- चक्र का डिज़ाइन अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के चक्र पर आधारित है।
- चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है।
- ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होगा।
- इस प्रस्ताव को विधानसभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

## UPSC Prelims PYQ : 2023

**प्रश्न: भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. कथन-I: भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मानक आकारों में से एक 600 मिमी * 400 मिमी है।
2. कथन-II: ध्वज की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण है
b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण नहीं है
c) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

**उत्तर: (d)**

# Focus on female employment to counter unemployment

**Indranil De**

Professor, Institute of Rural Management Anand, Gujarat

The difficulty in getting jobs and inflation were the two major issues that played a role in the results of the Lok Sabha Elections 2024, according to the Lokniti-CSDS pre-poll survey (*The Hindu*, April 11, 2024). The India Employment Report (IER) 2024, published by the Institute for Human Development and the International Labour Organization, also illustrated a rise in the unemployment rate from a little more than 2% in 2000 and 2012 to 5.8% in 2019. Unemployment reduced somewhat to 4.1% in 2022, although time-related underemployment was high at 7.5%. The labour force participation rate (LFPR) also fell from 61.6% in 2000 to 49.8% in 2018 but recovered halfway to 55.2% in 2022. But in this gloomy picture marked by unemployment and underemployment, there was a steep and steady upward trend of female LFPR from 24.6% in 2018 to 36.6% in 2022 in rural India. It also increased by around 3.5% from 20.4% in 2018 in urban areas. This is in contrast with male LFPR, which rose marginally by 2% in rural areas and almost stagnant in urban areas.

Female LFPR in India is low when compared to the world average of 53.4% (2019), and it has decreased from 38.9% in 2000 to 23.3% in 2018. Against this backdrop, the current increasing trend in female LFPR, especially a 12% rise in rural India during 2018-22, indicates an untapped opportunity for employment generation. Women have been engaged in unpaid family labour work in both rural and urban areas. While 9.3% of males were employed as unpaid family workers, the same was as high as 36.5% for females in 2022. Moreover, the difference between female and male unpaid family labour employment was 31.4% in rural areas against only 8.1% in urban areas. Hence, if appropriate strategies are taken, there is a much greater opportunity for female employment generation, especially in rural areas.

The choice of employment for earnings may be extremely gendered, which makes generating employment opportunities for females tricky. Our study on work conditions and employment for women in the slums of Bhuj, Gujarat, shows that women are more interested in engaging in traditional employment activities from home, such as *bandhani*, embroidery and fall beading, rather than other opportunities, including non-farm casual labour. The flexibility of work and the possibility of working from home were the major reasons for preferring traditional occupations despite their low income. The study also found that 30% of women were stuck to their traditional occupations due to the unavailability of other options. A lower rise of female LFPR in urban than rural areas during 2018-22, as shown in IER 2024, also indicates a lack of appropriate and gainful opportunities for females in urban areas. The opportunity to develop one's own enterprise was difficult due to limited access to capital and binding social norms where males of a particular community control the dominant business of the locality – tie and dye. Collectivising women under self-help groups (SHG), and, further, through federations may benefit women involved in traditional occupations. SHG women may be trained to acquire new skills, and federations may link women directly to the market for better returns. The Kutch Mahila Vikas Sangathan (KMVS), a local non-profit organisation, is working in the region towards this end.

A better female labour force participation rate can improve overall family income and welfare, especially in rural India

Traditional occupations are accepted by society as they conform to local gender norms. These occupations have emerged as the dominant choice of women. Traditional occupations support women's practical gender needs, such as managing both household work and earnings. However, they may not help in meeting strategic gender needs, such as challenging regressive gender norms. Moving out of their own dwelling and working in a professional environment increases women's agency and empowers them to meet strategic gender needs.

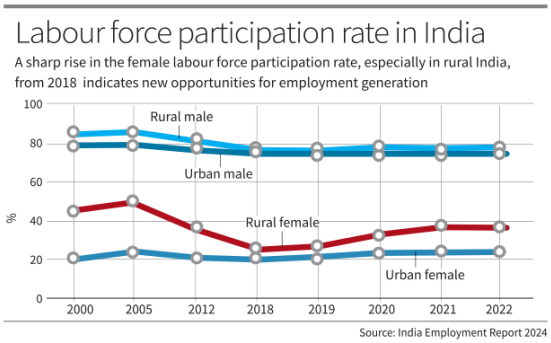


**The importance of market access**

The foray of women into male-dominated workspaces would increase competition for labour work. This competition can be avoided by generating new opportunities in previously neglected arenas. In a study on the relationship between the type of dominant irrigation source of a region (canal or groundwater) and women's empowerment (farm employment and decision-making abilities) in the villages in the Upper Gangetic Plains of Uttarakhand and Uttar Pradesh, we found that women's wages in farm labour work and decision-making abilities increased with the expansion of relatively less dominant source of irrigation and vice versa. Males may take more interest if more water is available through the dominant source of the region. Further, the expansion of canal irrigation during *Ziad* (summer slump season), when males had less interest in agriculture, positively affected female empowerment.

Additional non-conventional irrigation benefits women, as this writer's recent field visits to villages in West Bengal showed. Women have initiated farming, pisciculture, nursery and vermicompost after water is made available through ponds or tube wells in arid and monocropped regions. These women are part of an all-women water user's association supported by the West Bengal Accelerated Development of Minor Irrigation Project, Government of West Bengal. Availability of work near home has reduced female migration with the whole family and has increased family welfare. Male family members help in heavy activities that demand strength, such as ploughing or netting in ponds. In most tribal villages, women are barred from ploughing due to gender norms. Similar norms exist for netting in ponds. Women said that they could carry on without the help of male family members if they used hired tractors for ploughing and hired labour for netting. More market interaction empowers women by enabling them to circumvent gender norms and reduce dependency on male family members. Far away, in the Upper Gangetic Plains, a more vibrant water market was found to be associated with higher agency by women to influence the purchase of agricultural inputs.

The earnings of both men and women contribute to family income and welfare. Hence, the strategy to enhance women's workforce participation and reduce underutilisation of time can be possible by developing income-earning opportunities where males need not be confronted and driven out of the labour market. Women's work opportunities at or near home can enhance the family income and women's position in the family. Strikingly, a woman in West Bengal was proud that she could lend money to her husband to buy agricultural inputs. In another study in the slums of Kolkata, it was observed that women's participation in the workforce has reduced economic vulnerability and improved resilience during the COVID-19 pandemic.

**Need for a better work environment**

At the same time, participation in work outside the home should be focused. This has a more direct impact on women's empowerment. However, a long-term strategy is required to develop a better work environment for women. Safety and basic facilities in the workplace (toilets and crèches) should be made available. Public policy should mandate these facilities in small- and medium-manufacturing or business units.

A strategy of focusing on the improvement of female LFPR would improve overall employment and the family income. In rural areas, public policy should help women by providing more access to resources (such as water) and markets (to buy inputs and implements and to sell produce). In urban areas, better facilities in the workplace should be mandated. Collectivising women and federating collectives in rural and urban India under planned economic activities will be most helpful. The *Lakhpati Didi* programme aiming at raising an SHG woman's annual income to ₹1 lakh or above may pave the way.

*The views expressed are personal*

**GS Paper 03 :** भारतीय अर्थव्यवस्था - विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

**PYQ: (UPSC CSE (M) GS-3 2022) :** हाल के दिनों में आर्थिक वृद्धि श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुई है। इस कथन की व्याख्या करें। उस वृद्धि पैटर्न का सुझाव दें जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक नौकरियों के सृजन की ओर ले जाएगा। **(250 w /15 m)**

**Practice Question** हाल ही में रोजगार रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) में वृद्धि के निहितार्थों पर चर्चा करें। देश में बेरोजगारी और अल्परोजगार के मुद्दों को हल करने के लिए इस प्रवृत्ति का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

**(250 w/15m)**

## संदर्भ

- लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और भारत रोजगार रिपोर्ट (आईईआर) 2024 ने भारत में रोजगार की चुनौतियों, खासकर बढ़ती बेरोजगारी और अल्परोजगार को उजागर किया है।
- महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) कम होने के बावजूद, हाल के रुझान इसमें वृद्धि दर्शाते हैं, जिससे महिलाओं के लिए लक्षित रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तीकरण के अवसर सामने आ रहे हैं।

## परिचय

- नौकरी पाने में कठिनाई और मुद्रास्फीति लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दे थे।
- लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण ने इन चिंताओं को उजागर किया।
- मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट (आईईआर) 2024 ने विस्तृत रोजगार आँकड़े प्रदान किए।

## महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) क्या है?

- महिला श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल का हिस्सा बनने वाली महिलाओं की संख्या और कामकाजी आयु (15 वर्ष से अधिक आयु) में महिलाओं की संख्या का अनुपात है।
- एक महिला को श्रम बल का हिस्सा तभी माना जाता है जब वह या तो कार्यरत हो या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रही हो।

## महिला बेरोज़गारी के रुझान

- एलएफपीआर में ग्रामीण-शहरी असमानताएँ: बेरोज़गारी 2000 और 2012 में 2% से थोड़ी अधिक से बढ़कर 2019 में 5.8% हो गई।
  o यह 2022 में थोड़ा कम होकर 4.1% हो गई, हालाँकि समय-संबंधित अल्परोज़गार 7.5% पर उच्च था।
  o श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2000 में 61.6% से गिरकर 2018 में 49.8% हो गई, लेकिन 2022 में आधे से ज़्यादा बढ़कर 55.2% हो गई।
- पारंपरिक व्यवसायों का प्रभाव: कई महिलाएँ लचीलेपन और घर से काम करने की क्षमता के कारण बांधनी और कढ़ाई जैसे पारंपरिक व्यवसायों को पसंद करती हैं। यह विकल्प सामाजिक मानदंडों और अन्य अवसरों की तुलना में कम आय के बावजूद इन भूमिकाओं की कथित सुरक्षा से प्रभावित है।
- नीति और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका: एसएचजी और संघों जैसी पहलों ने कौशल प्रशिक्षण और बाजार संपर्क प्रदान करके पारंपरिक व्यवसायों में महिलाओं का समर्थन किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य स्थानीय संदर्भों में महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

## महिला रोजगार में बाधाएँ और अवसर

- शहरी रोजगार में बाधाएँ: शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक भूमिकाओं के बाहर महिलाओं के लिए सीमित लाभकारी रोजगार विकल्प जैसी चुनौतियाँ हैं। यह लैंगिक अपेक्षाओं और पूंजी तक पहुँच से और भी जटिल हो जाता है, जो महिलाओं के बीच उद्यमशीलता के उपक्रमों को प्रतिबंधित करता है।
- व्यापक नीतियों की आवश्यकता: सार्वजनिक नीति को कृषि और संबद्ध गतिविधियों का समर्थन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और बाज़ार जैसे संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में, कार्यस्थलों में शौचालय और क्रेच जैसी अनिवार्य सुविधाएँ काम करने की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आर्थिक सशक्तिकरण और परिवार कल्याण: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी न केवल पारिवारिक आय में योगदान करती है, बल्कि घर के भीतर उनकी स्थिति को भी बढ़ाती है। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं की आय आर्थिक मंदी, जैसे कि COVID-19 महामारी के दौरान लचीलापन बढ़ाती है।

## नीतिगत सिफारिशें

- सामूहिकीकरण और बाजार तक पहुँच: एसएचजी और संघों के माध्यम से सामूहिक प्रयास महिलाओं के लिए आर्थिक हस्तक्षेप के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म सामूहिक सौदेबाजी, कौशल विकास और बड़े बाजारों तक पहुँच को सक्षम करते हैं, जिससे आर्थिक परिणाम बेहतर होते हैं।
- सक्षम वातावरण बनाना: सुरक्षा उपायों और आवश्यक सुविधाओं के साथ एक अनुकूल कार्य वातावरण विकसित करना अधिक महिलाओं को कार्यबल में प्रवेश करने और बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सुरक्षित कार्यस्थल, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ और चाइल्डकैअर सहायता के प्रावधान शामिल हैं।

## निष्कर्ष

- महिला एलएफपीआर में सुधार पर एक केंद्रित रणनीति समग्र रोजगार और पारिवारिक आय को बढ़ा सकती है।
- संसाधनों, बाजारों और बेहतर कार्य वातावरण तक बेहतर पहुँच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है।
- नीतियों को एसएचजी और संघों के माध्यम से विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं का समर्थन करना चाहिए।

## महत्वपूर्ण पदों

- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):**
  - एलएफपीआर कार्यशील आयु वर्ग की आबादी (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) का प्रतिशत है जो या तो कार्यरत है या बेरोजगार है, लेकिन रोजगार के लिए इच्छुक है और इसकी तलाश कर रहा है।

- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):**
  - डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **बेरोजगारी दर (यूआर):**
  - यूआर को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **गतिविधि स्थिति**
  - o किसी व्यक्ति की गतिविधि स्थिति निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो इसे व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है।

**o गतिविधि स्थिति के प्रकार:**

- मुख्य गतिविधि स्थिति (PS): वह गतिविधि स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (मुख्य समय मानदंड) बिताया, उसे व्यक्ति की सामान्य मुख्य गतिविधि स्थिति माना जाता था।
- सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति (SS): वह गतिविधि स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपनी सामान्य मुख्य स्थिति के अलावा, सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के लिए 30 दिनों या उससे अधिक समय के लिए कुछ आर्थिक गतिविधि करता है, उसे व्यक्ति की सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति माना जाता था।
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के रूप में जाना जाता है।

## बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं?

| बेरोज़गारी का प्रकार | विवरण |
|---|---|
| छिपी हुई बेरोज़गारी | ज़रूरत से ज़्यादा लोग रोज़गार में हैं, मुख्य रूप से कृषि और असंगठित क्षेत्रों में। |
| मौसमी बेरोज़गारी | साल के खास मौसमों में होता है, अक्सर कृषि मज़दूरों को प्रभावित करता है जो साल भर काम नहीं करते। |
| संरचनात्मक बेरोज़गारी | उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होता है। |
| चक्रीय बेरोज़गारी | आर्थिक चक्रों से जुड़ा हुआ है, मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और विकास की अवधि में घटती है। |
| तकनीकी बेरोज़गारी | तकनीकी परिवर्तनों के कारण नौकरी छूटना। भारत ने स्वचालन से महत्वपूर्ण प्रभाव देखा है। |
| घर्षण बेरोज़गारी | इसमें समय अंतराल शामिल होता है जब व्यक्ति नौकरी की तलाश करते हैं या नौकरी बदलते हैं, अक्सर स्वैच्छिक और नौकरी की कमी के कारण नहीं। |
| कमज़ोर रोज़गार | कानूनी सुरक्षा के बिना अनौपचारिक, अनुबंध-रहित काम, अक्सर बिना रिकॉर्ड किए रोज़गार की ओर ले जाता है। |

## भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कम होने के क्या कारण हैं?

- अनौपचारिकता का उच्च स्तर- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की 95% से अधिक कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक श्रमिक हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जाल की अनुपस्थिति महिलाओं को श्रम बल में भाग लेने से हतोत्साहित करती है।
- विनिर्माण में कमी-विनिर्माण में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की कमी और महिलाओं के लिए सेवाओं में नौकरियों की सीमित संख्या ने भी भारत में FLFPR को दबा दिया है।
- लिंग वेतन अंतर और ग्लास सीलिंग- आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, भारत में पूर्णकालिक कर्मचारियों की औसत आय में सबसे बड़ा लिंग अंतर है। कार्यस्थल पर इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ FLFPR पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- गुलाबी नौकरियाँ- 'लिंग आधारित व्यवसायों' के बारे में सामाजिक धारणाएँ महिलाओं की भूमिका को नर्सिंग, शिक्षण, स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि जैसे विशिष्ट नौकरी प्रोफाइल तक सीमित करती हैं। भारी इंजीनियरिंग, कानून प्रवर्तन, सशस्त्र बलों आदि जैसे कई व्यवसायों में महिलाओं के प्रवेश के लिए मूर्त और अमूर्त बाधाएँ हैं।

- सांस्कृतिक प्रथाएँ- अवैतनिक देखभाल, बच्चों की देखभाल और घरेलू काम-काज ने महिलाओं की श्रम शक्ति में भाग लेने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। पितृसत्तात्मक समाज में, कई महिलाओं को शादी के बाद काम करने की अनुमति नहीं है।
- घरेलू आय में वृद्धि- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू आय में वृद्धि ने महिलाओं को नौकरी न करने का विकल्प प्रदान किया है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ- महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा की उच्च घटनाएँ महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तरह रात में काम करने से हतोत्साहित करती हैं। इसके अलावा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले महिलाओं को श्रम शक्ति से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं।
- शिक्षित बेरोज़गारी- माध्यमिक शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में देखा गया है कि महिलाएँ उच्च शिक्षा के लिए जा रही हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा के स्तर से मेल खाने वाली नौकरियों की उपलब्धता की कमी भी कम FLFPR में योगदान देती है।
- कानूनी रूप से स्वीकृत प्रतिबंध- कई राज्य कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में खतरनाक नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना जारी रखते हैं।
- उदाहरण के लिए- महिलाओं को पत्थर काटने की मशीनों, बॉयलर की दुकान के फर्श आदि पर काम करने की अनुमति नहीं है।
- राजनीतिक शून्यता- वर्तमान लोकसभा में केवल 14.4% महिलाएँ हैं, जबकि भारतीय जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 50% है। लैंगिक दृष्टिकोण की कमी एक व्यापक नीति के निर्माण को बाधित करती है जो आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

**महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने का क्या महत्व है?**

- आर्थिक बढ़ावा- आईएमएफ के अनुसार, कार्यबल में लैंगिक समानता भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27% सुधार कर सकती है।
- गरीबी से निपटना- यह गरीबी के स्त्रीकरण की घटना से निपटने में मदद करता है, जो महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक अनौपचारिक काम का परिणाम है।
- सामाजिक संकेतकों में सुधार- अधिक महिलाओं को औपचारिक कार्यबल में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने से शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) जैसे संकेतकों में सुधार होगा।
- आत्मविश्वास और गरिमा- वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को परिवार नियोजन जैसे निर्णय लेने में अधिक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।
- वैश्विक प्रतिबद्धताएँ- एफएलएफपीआर में सुधार एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन), एसडीजी 5 (लैंगिक समानता), एसडीजी 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) और एसडीजी 10 (असमानताओं में कमी) की उपलब्धियों से संबंधित है।

**महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी योजनाएं क्या हैं?**

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

2. वन स्टॉप सेंटर योजना
3. स्वाधार गृह
4. नारी शक्ति पुरस्कार
5. महिला पुलिस स्वयंसेवक
6. महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)
7. निर्भया निधि।

# Mapping : Major Hill Ranges of India

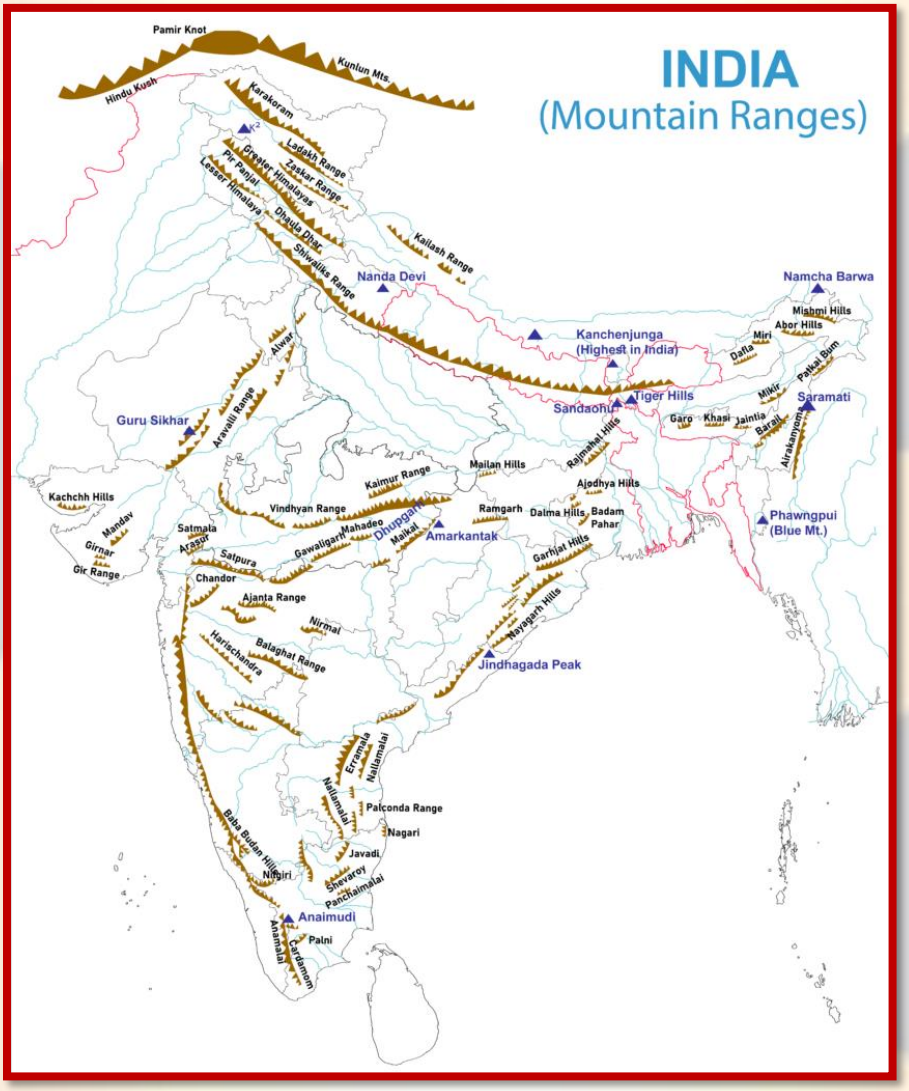


1. अरावली पहाड़ियाँ
2. विंध्य पर्वतमाला
3. सतपुड़ा पर्वतमाला
4. पश्चिमी घाट

## 5. पूर्वी घाट

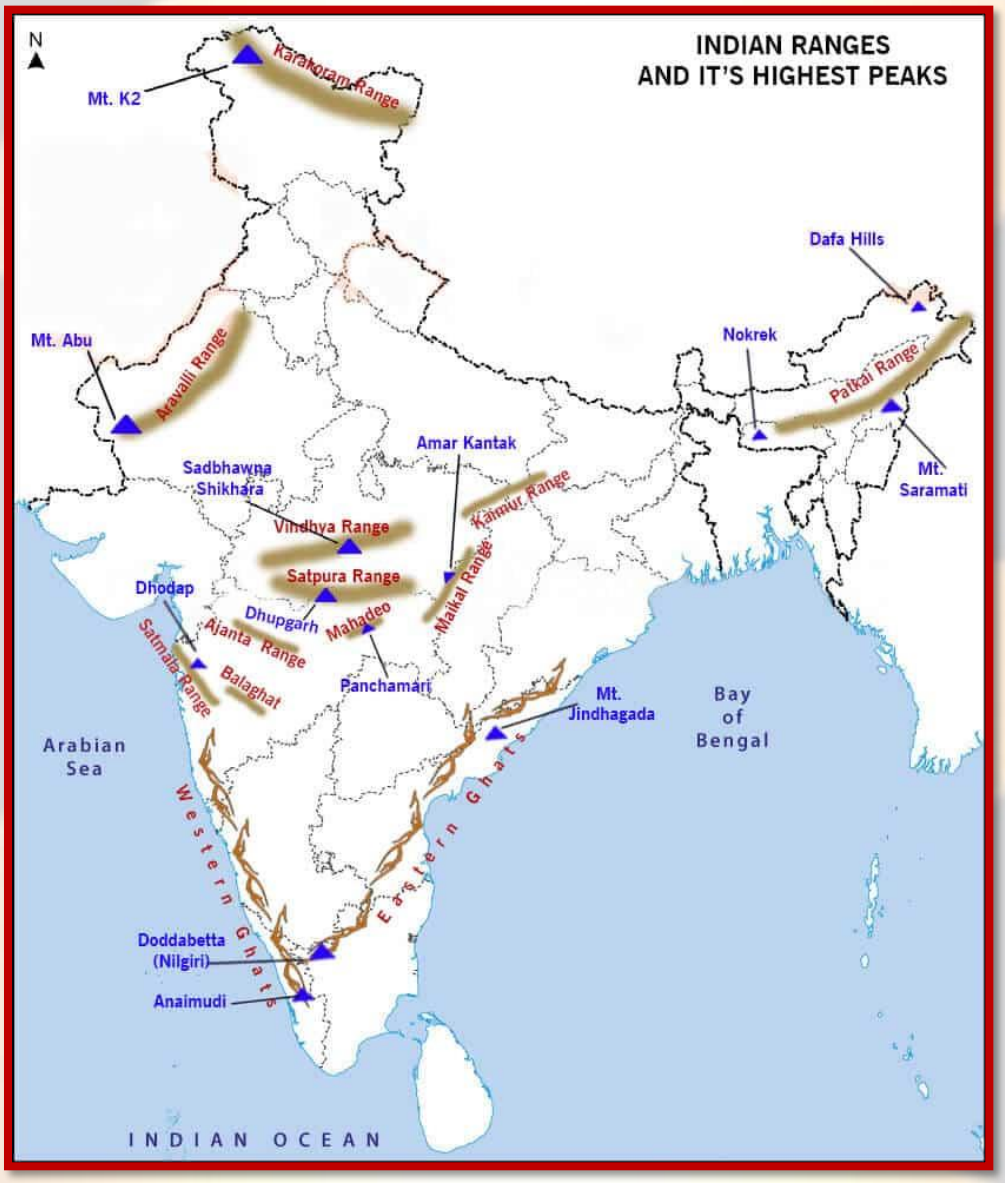


### अरावली पहाड़ियाँ

- वे गुजरात (पालनपुर में) से निकलती हैं और हरियाणा तक फैली हुई हैं। वे दिल्ली रिज में समाप्त होती हैं।
- उनकी अधिकतम सीमा 800 किमी है
- वे पुरानी तह पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने टेक्टोनिक पहाड़ों में से एक हैं।
- अरावली को बनाने वाली चट्टानें 2 अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं।

- अन्य तह पहाड़ों के विपरीत, अरावली की औसत ऊँचाई केवल 400-600 मीटर के बीच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके भूवैज्ञानिक इतिहास में वे अपक्षय और क्षरण की प्रक्रियाओं के अधीन थे।
- केवल कुछ चोटियाँ 1000 मीटर से ऊपर की ऊँचाई तक पहुँचती हैं। इनमें शामिल हैं - माउंट गुरुशिखर (1722 मीटर, अरावली का सबसे ऊँचा बिंदु), माउंट आबू (1158 मीटर, यह एक पठार का हिस्सा है)।
- भूवैज्ञानिक रूप से, वे मुख्य रूप से धारवाड़ आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हैं।
- उनमें भारत के सबसे बड़े संगमरमर के भंडार हैं।
- बनास, लूनी, साबरमती नदियाँ अरावली में उत्पन्न होती हैं। बनास चंबल की एक सहायक नदी है। लूनी एक अल्पकालिक नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त होती है।
- इनमें कई दर्रे हैं जो इनसे होकर गुजरते हैं, खासकर उदयपुर और अजमेर के बीच जैसे पिपलीघाट, देवर, देसूरी, आदि।
- इनमें कई झीलें भी हैं जैसे सांभर झील (भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा जल निकाय), ढेबर झील (अरावली के दक्षिण में), जयसमंद झील (जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में), आदि।

**विंध्य पर्वतमाला**

- ये गैर-विवर्तनिक पर्वत हैं, इनका निर्माण प्लेटों के टकराव के कारण नहीं बल्कि दक्षिण में नर्मदा रिफ्ट घाटी (NRV) के नीचे की ओर फॉल्ट होने के कारण हुआ है।
- ये गुजरात के भरूच से बिहार के सासाराम तक 1200 किमी तक फैले हुए हैं।
- भूवैज्ञानिक रूप से, ये अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों से छोटे हैं।
- इनकी औसत ऊँचाई 300-650 मीटर के बीच है।
- ये पुरानी प्रोटेरोज़ोइक चट्टानों से बने हैं। इन्हें किम्बरलाइट पाइप्स (हीरे के भंडार) द्वारा काटा गया है
- ये स्थानीय नामों जैसे पन्ना, कैमूर, रीवा आदि से जाने जाते हैं।
- ये NRV से खड़ी, तीखी ढलानों के रूप में उठते हैं जिन्हें एस्केरपमेंट कहा जाता है। ये एस्केरपमेंट कैमूर और पन्ना क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित हैं।

**सतपुड़ा पर्वतमाला**

- सतपुड़ा पर्वतमाला सतपुड़ा, महादेव और मैकाल पहाड़ियों का एक संयोजन है।
- सतपुड़ा पहाड़ियाँ टेक्टोनिक पहाड़ियाँ हैं, जो लगभग 1.6 अरब साल पहले तह और संरचनात्मक उत्थान के परिणामस्वरूप बनी थीं। वे एक हॉर्स्ट भू-आकृति हैं।
- वे लगभग 900 किमी की दूरी तक फैले हुए हैं।
- महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पहाड़ियों के पूर्व में स्थित हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊँचा स्थान है। धूपगढ़ (1350 मीटर) पचमढ़ी की सबसे ऊँची चोटी है।

- मैकला पहाड़ियाँ महादेव पहाड़ियों के पूर्व में स्थित हैं। अमरकंटक पठार मैकला पहाड़ियों का एक हिस्सा है। यह लगभग 1127 मीटर ऊँचा है।
- पठार में नर्मदा और सोन की जल निकासी प्रणालियाँ हैं, इसलिए इसमें बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ अरब सागर में भी जल निकासी होती है।
- ये ज्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित हैं।
- गोंडवाना चट्टानों की उपस्थिति के कारण ये पहाड़ियाँ बॉक्साइट से समृद्ध हैं।
- नर्मदा पर धुआँधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है।

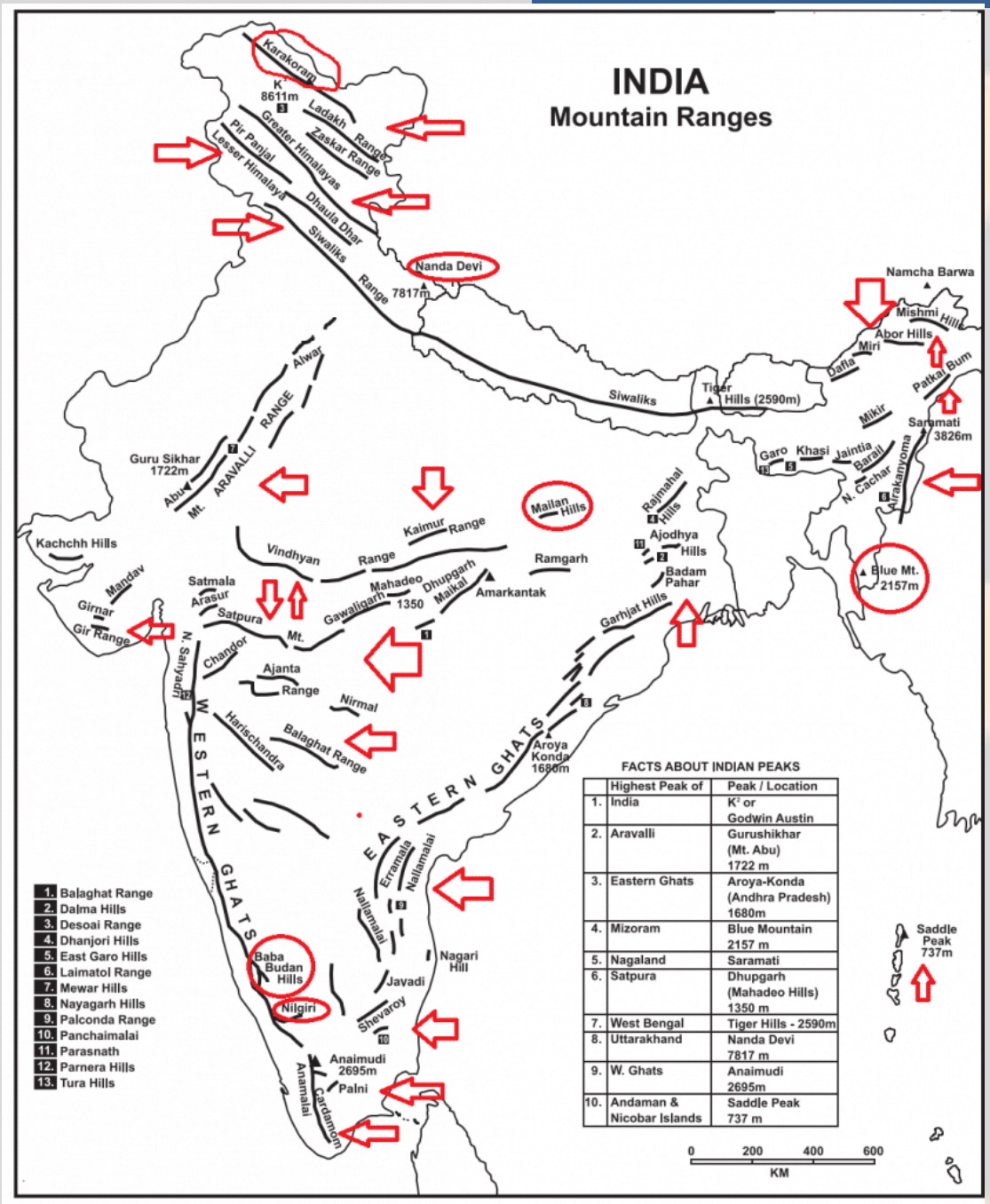


| | Highest Peak of | Peak / Location |
|---|---|---|
| 1. | India | $K^2$ or Godwin Austin |
| 2. | Aravalli | Gurushikhar (Mt. Abu) 1722 m |
| 3. | Eastern Ghats | Aroya-Konda (Andhra Pradesh) 1680m |
| 4. | Mizoram | Blue Mountain 2157 m |
| 5. | Nagaland | Saramati |
| 6. | Satpura | Dhupgarh (Mahadeo Hills) 1350 m |
| 7. | West Bengal | Tiger Hills - 2590m |
| 8. | Uttarakhand | Nanda Devi 7817 m |
| 9. | W. Ghats | Anaimudi 2695m |
| 10. | Andaman & Nicobar Islands | Saddle Peak 737 m |

| | |
|---|---|
| मैकाल रेंज | सतपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग (म.प्र.) |
| कैमूर रेंज | म.प्र., उ.प्र. और बिहार में विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी भाग, सोन नदी के समानांतर |
| महादेव रेंज | मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला का मध्य भाग है। सबसे ऊंची चोटी: धूपगढ़ |
| अजंता रेंज | महाराष्ट्र, तापी नदी के दक्षिण में गुप्त काल की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला की गुफाएं |
| राजमहल पहाड़ी | झारखंड में लावा बेसाल्टिक चट्टानों से बना |

| | |
|---|---|
| | गंगा विभाजन बिंदु |
| गारो खासी जयंतिया पहाड़ी | मेघालय में सतत पर्वत श्रृंखला |
| मिकिर पहाड़ी | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम) के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का एक समूह, कार्बी आंगलोंग पठार का एक भाग |
| अबोर हिल्स | अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, चीन की सीमा के पास, मिश्मी और मिरी पहाड़ियों से घिरी हुई हैं, जिनका जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग नदी है। |
| मिशमी हिल्स | अरुणाचल प्रदेश में स्थित, जिसका उत्तरी और पूर्वी भाग चीन से मिलता है<br>पूर्वोत्तर हिमालय और इंडो-बर्मा पर्वतमाला के संगम पर स्थित |
| पटकाई रेंज | पूर्वांचल रेंज के नाम से भी जानी जाने वाली इस रेंज में तीन प्रमुख पहाड़ियाँ शामिल हैं - पटकाई-बम, गारो-खासी-जयंतिया और लुशाई पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ भारत की बर्मा से लगती उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। |
| कोबरू हिल | माउंट कौपालु के नाम से भी जाना जाने वाला यह पर्वत मणिपुर के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है और मणिपुरी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह देवता लेनिंगथौ कुबरू और देवी कोनु का निवास स्थान है। |
| मिजो हिल्स (लुशाई हिल्स) | पटकाई पर्वतमाला का कुछ भाग मिजोरम में तथा आंशिक रूप से त्रिपुरा में |
| डालमा हिल्स | जमशेदपुर में स्थित, यह दलमा राष्ट्रीय उद्यान और लौह अयस्क और मैंगनीज जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। |
| धनजोरी पहाड़ियाँ | झारखंड |
| गिरनार पहाड़ियाँ | गुजरात |
| बाबा बुदन गिरि | कर्नाटक |
| हरिश्चंद्र | पुणे में, गोदावरी और कृष्णा के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता है<br>लावा से बनी पहाड़ियाँ |
| बालाघाट रेंज | बीडब्ल्यू एमपी और महाराष्ट्र, मैंगनीज भंडार के लिए प्रसिद्ध |
| चिल्पी श्रृंखला | एमपी |
| तालचेर श्रृंखला | ओडिशा, बिटुमिनस कोयले से समृद्ध |
| चैंपियन श्रृंखला | कर्नाटक, धारावाड़ काल, सोने से समृद्ध (इसमें कोलार की खदानें शामिल हैं) |
| नीलगिरी पहाड़ियाँ | नीले पहाड़ों के रूप में संदर्भित, कर्नाटक और केरल पहाड़ियों के जंक्शन पर तमिलनाडु के पश्चिमी भाग में पहाड़ों की एक श्रृंखला उत्तर में कर्नाटक पठार से मोयार नदी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों से पालघाट गैप द्वारा अलग होती है। |
| पलानी हिल्स | पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पूर्व की ओर विस्तार पश्चिम में उच्च अन्नामलाई पर्वतमाला से सटा हुआ है, तथा पूर्व में तमिलनाडु के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। |
| अनामलाई पहाड़ियाँ | एलीफेंट हिल के नाम से भी जाना जाने वाला यह पर्वत तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट में स्थित पर्वतों की एक श्रृंखला है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है। |
| इलायची पहाड़ियाँ | दक्षिण-पूर्व केरल और दक्षिण-पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा |
| पचमलाई पहाड़ियाँ | तमिलनाडु में इसे पचाईस, पूर्वी घाट के नाम से भी जाना जाता है |
| पारसनाथ पहाड़ियाँ | पारसनाथ, पारसनाथ पर्वतमाला में एक पर्वत शिखर है। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। |